

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०, बागेश्वर (कपकोट)।

फैक्स नं० 05963-220127

ई-मेल:- eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांक:- ४१। वनभूमि/पी०एम०जी०एस०वाई० / 2017-18,

दिनांक:- 21-12-2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इन्दिरानगर, फ़ौरिस्ट कालोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषय- जनपद-बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या
FP/UK/ROAD/28919/2017 बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के कि०मी० 33 से
किरोली मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के
EDS dated 19-09-2018

महोदय,

वनभूमि प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/28919/2017 बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग
के कि०मी० 33 से किरोली मोटर मार्ग में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण आनलाईन कर दिया गया
है, एवं आफलाईन एक प्रति प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को एवं तीन प्रतियों में आपके कार्यालय को
संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०-2, पी०एम०जी०एस०वाई०,
कपकोट

कार्यालय अपर प्रमुख वन सहायक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्स्टीटयूट फॉर स्ट्रैटेजी, उत्तरप्रदेश, देहरादून।

सेवा में,

अधिसारी अधिवक्ता,

पीओआरओ 1।

पीएमएनपीएसआरओ, काकोट।

विषय- जनपद-गोरख काकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी 33 से किमी 35 के किमी मोटर मार्ग हेतु EDS के निर्माण
के सम्बन्ध में। EDAK/ROAD/289192017

संदर्भ- मासु उत्तार पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS
दिनांक 10-08-2018

महोदय,

भारत सरकार, पर्यटन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त
विषयक संचालित पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया पत्र में
उल्लिखित स्वर से संचालित विभिन्न विस्तृतों की सूचनाओं और लार्डन करते हुए तीन डार्ड प्रतियों में
शीघ्रतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, एवं वन प्रभाग को स्तर से प्रश्न की जाने वाली सूचनाओं हेतु
वन प्रभाग से सामंजस्य स्थापित कर सूचनाएं शीघ्र प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करवाये।

उल्लेखनीय है, कि आपके द्वारा सूचना सम्बन्ध उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में भारत सरकार
द्वारा प्रस्ताव को निरस्त भी किया जा सकता है। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपके खण्ड की होगी।

सहायक-योजनाएँ